द्वितीय राष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण

दिनांक 1 फरवरी, 2006
नई दिल्ली

आज यहां आपके बीच आकर मुझे खुशी हो रही है। मैं आप में से कई लोगों को समय-समय पर मिलता रहा हूं और देश के विभिन्न भागों में मीडिया के लोगों के साथ बातचीत करने का मुझे सुखद अनुभव हुआ है। किन्तु, लगभग एक साल के बाद पहली बार मुझे किसी राष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर मिल पाया है। इस अवधि में केन्द्र सरकार ने जिस स्तर पर अपने कार्यकलापों को चलाया है, उसे देखते हुए सही मायने में यह एक उल्लेखनीय अवधि रही है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार लगभग उन सभी महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने में समर्थ रही है जो हमने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जरिए लोगों से किए थे। हमने अपनी सरकार के कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर जनता के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और दूसरी रिपोर्ट भी मेरे कार्यालय द्वारा तैयार की गई है तथा आपको परिचालित की जा रही है।

यू.पी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जरिए देश से छह अहम वादे किए थेः

पहला, हम सामाजिक मेल-मिलाप को कायम रखेंगे और उसे बढ़ावा देंगे तथा हर तरह की साम्प्रदायिकता का डटकर मुकाबला करेंगे। हमने ऐसा किया भी है और हम ऐसा करते रहेंगे। हमने अपने संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षवाद और बहुलवाद के मूल्यों और सिद्धांतों में सभी लोगों की आस्था और विश्वास को फिर से जगाया है। हमने उन्हें कानून-सम्मत शासन चलाने का और साथ ही सामाजिक न्याय दिलाने का फिर से यकीन दिलाया है। आज सभी अल्पसंख्यकों में गर्व के साथ, बेफिक्र होकर, आत्म-सम्मान के साथ जीने की एक नई भावना मौजूद है। हमने इनमें असंतोष की भावना को खत्म किया है और अपनेपन की भावना को फिर से जगाया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण पर जोर देने के लिए हमने एक नया अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का सृजन किया है।

दूसरा, हमने 7% से 8% की विकास दर बनाए रखने का वादा किया है। हमने 7% से अधिक की विकास दर बनाए रखी है और हम इसमें और गति लाएंगे। इससे अधिक रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया है। "रोजगार बढ़ाओ" हमारी सरकार का नारा है। कठिन हालात के बावजूद हम दामों में बढ़ोतरी को रोकने में भी कामयाब रहे हैं और इसका श्रेय आप सभी को जाता है।

तीसरा, हमने अपने किसानों, खेत मजदूरों और कामगारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को, अधिक सुरक्षित भविष्य का यकीन दिलाया। हमने उनके लिए जो कदम उठाए हैं, खासकर भारत निर्माण और देहाती इलाकों में पढ़ाई, सेहत और रोजगार के कार्यक्रम, इसके जरिए उनका भविष्य सुनहरा होगा। "ग्रामीण इलाकों के लिए नई पहल" के जरिए हमने किसानों के भविष्य को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें ग्रामीण लोगों के लिए कर्ज में भारी बढ़ोतरी करना और सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए धनराशि देना शामिल है।

चौथा, हम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्हें राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और कानूनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए। इन सभी क्षेत्रों में हमने बड़े कदम उठाए हैं। हमने महिलाओं की घरेलू हिंसा से हिफ़ाजत करने और उन्हें सम्पत्ति में उत्तराधिकार दिलाने के लिए कानून बनाया है। हमने महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए कार्यक्रमों को मजबूत किया है। हमने बालिकाओं और युवा लड़कियों की पढ़ाई तथा सेहत पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी की है। हालांकि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि शासन की सभी संस्थाओं तथा जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, परन्तु मुझे खेद है कि हम महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं करा पाए हैं। फिर भी, हम निकट भविष्य में संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिलाने के लिए हर कोशिश करेंगे।

पांचवां, हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने का वादा किया है, खासकर शिक्षा और रोजगार के माध्यम से। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अभी तक हाल में जो भी सरकार सत्ता में आई है, हमने इस दिशा में उनसे कहीं अधिक काम किया है। पिछले दो सालों में सर्व शिक्षा अभियान के लिए धनराशि को दोगुना कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। दलित और आदिवासी परिवारों की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं। अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एम.फिल और पी.एच.डी. शिक्षा के लिए राजीव गांधी वज़ीफा शुरू किया गया है।

आरक्षित पदों में खाली स्थानों को भरकर हमने अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों को केन्द्र सरकार में 30,000 नौकरियां दी हैं। हम जंगलों में आदिवासी लोगों को जमीन के हक दिलाने के लिए कानून को अमल में लाए हैं। इस अकेले कदम से करोड़ों आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा जो जमीन से बेदखल होने के डर से बेफिक्र होकर जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके साथ ही, हम अपने पर्यावरण की हिफ़ाजत के लिए भी कदम उठाएंगे। आखिरकार, बेहतर जंगल वे ही हैं जिनकी देखभाल हमारे आदिवासी भाई-बहनों द्वारा की जाती है। अल्पसंख्यकों के लिए एक नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों की पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि केवल शिक्षा ही लोगों की तरक्की का अहम जरिया है। धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की भलाई पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। कई दशकों में पहली बार एक समिति अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक हालात की जांच कर रही है। मैं समझता हूँ कि इन सभी कदमों से हमारे समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों में अधिकार हासिल करने की एक नई भावना पैदा हुई है।

आखिरी, हमने अपने उद्यमियों, व्यापारियों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य व्यवसायियों की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करने का वादा किया। भारत की तेज प्रगति की ओर विश्व की निगाहें दौड़ी हैं। आज देश और विदेश के बड़े-बड़े उद्योगपति और व्यवसायी हमारे देश के भविष्य के बारे में बहुत अधिक आशावान हैं। हमने अपने विनिर्माण क्षेत्र में फिर से नई जान डालने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई सालों बाद, औद्योगिक उत्पादन बढ़कर फिर से दो आंकड़ों के करीब पहुंच गया है जो अपने आप में एक रिकार्ड है। पिछली बार ऐसा 1995-96 में हुआ था जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी।

हमारी सरकार ने सभी लोगों के लिए समान रूप से विकास पर लगातार ध्यान देकर लाखों भारतीयों की उम्मीदों को फिर से जगाया है। हम रोजगार पैदा करने को सबसे ज्यादा तरजीह देते आ रहे हैं। इसके लिए हमने खास तौर पर कृषि तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार पैदा करने पर जोर दिया है। हमारी पांच बड़ी पहलों से न केवल भारत की तस्वीर बदलेगी बल्कि आम लोगों की जिन्दगी में भी बदलाव आएगा। ये पहल हैं:-

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
- भारत निर्माण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को शुरू में अधिक पिछड़े 200 जिलों में लागू किया जा रहा है और इसके बाद इसे धीरे-धीरे सारे देश में लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। दुनिया के शायद ही किसी देश में इस तरह की गारंटी है। हमारी ही पार्टी ने रोजगार की गारंटी दी है। सोनिया जी ने ही इस विधेयक को पारित कराने में अहम भूमिका अदा की।

हमारी सरकार गांवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की ओर काफी ध्यान देती रही है। **भारत निर्माण** के अधीन हरेक गांव में पक्की सड़क, पीने का पानी, बिजली और टेलीफोन होगा। हम ऐसा सन् 2009 तक कर लेंगे। इसके अलावा, हम 100 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि के लिए सिंचाई सुविधा मुहैया कराएंगे और 60 लाख घर बनवाएंगे। **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** के तहत हम सन् 2009 तक देश भर में सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। **राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन** देश के शहरों को विश्व-स्तरीय बनाने का हमारा एक प्रयास है। हालांकि, हमारी अधिकांश जनता अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, फिर भी वह दिन दूर नहीं है जब लगभग पचास फीसदी लोग शहरी इलाकों में रहने लगेंगे। हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे शहर और कस्बे, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएं और उनके पास विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा हो। दिल्ली मेट्रो की सफलता और लोकप्रियता से अन्य दूसरे शहरों को भी बेहतर शहरी परिवहन की मांग के साथ आगे आने के लिए बढ़ावा मिला है। हम यह देखेंगे कि अगले कुछेक सालों में हमारे शहरों में बड़ी मात्रा में निवेश हो। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नया निवेश होगा और शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर बनेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्थिति काफी उत्साहजनक है। सड़कों पर काफी काम हो रहा है। हम अगले सात सालों में, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम में, 1,70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश होने की उम्मीद करते हैं। हमारे हवाई अड्डों पर हवाई उड़ानों की चहल-पहल है। हवाई अड्डे भी आधुनिक बनाए जा रहे हैं और हैदराबाद तथा बंगलौर के हवाई अड्डों को जल्दी ही नए हवाई अड्डे मिलेंगे। रेलवे में न केवल सराहनीय ढंग से कार्य चल रहा है बल्कि रेलवे के पास एक महत्वाकांक्षी “Frieght Corridor Project” भी है। 25,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना, मालगाड़ी यातायात के लिए एक वरदान साबित होगी। बिजली सेक्टर की परेशानियों पर हम जल्दी ही ध्यान देंगे और मुझे विश्वास है कि इसकी परेशानियों का स्थाई हल निकाल लेंगे।

हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा के माहौल में भी सुधार किया है। हमने पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर और दूसरे कई गड़बड़ी वाले इलाकों में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम किया है। राजनीतिक जीवन की मुख्यधारा से बाहर रहने वाले सभी वर्गों से हम बातचीत कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल हो सके। ऐसा हमने अपने देश के हितों से समझौता किए बगैर किया है। हम राष्ट्र-विरोधी और विघटनकारी ताकतों का निरंतर मुकाबला करते रहेंगे। हम आतंकवाद को परास्त करेंगे। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है कि भारत के लोगों ने हर बार यह दिखाया है कि हमारे देश में राजनीतिक सत्ता केवल मत पेटी से निकलती है न कि बंदूक की नली से! मैं पूरी तरह समझता हूं कि देश के अनेक हिस्सों में नक्सलवाद एक समस्या बना हुआ है। यद्यपि हिंसा की निंदा की जानी चाहिए और हमारे पुलिस बल इसका डटकर मुकाबला करेंगे, फिर भी हम इसके मूल कारणों—घोर गरीबी, निरक्षरता और भूमिहीनता पर भी ध्यान देंगे।

दुनिया के देश हमारे साथ ज्यादा दोस्ताना तरीके से पेश आएं, इसके लिए भी हमारी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। हमने अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन समेत अन्य कई पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार किया है। हम यह जानते हुए पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त बातचीत कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया में हम केवल इतिहास के साझेदार ही नहीं रहे हैं बल्कि भविष्य के और भाग्य बनाने के भी साझेदार हैं। हमारे पड़ोसी देशों की तरक्की और खुशहाली हमारे हित में है।

हमने पूर्व एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के साथ अपनी अर्थ-व्यवस्था को जोड़ने के लिए बड़ी पहलें की हैं। हमारे पूर्व की ओर के देशों ने एक बार फिर हमें अपने साथ शामिल किया है और हमें एक नया एशियाई समुदाय बनाने के लिए न्यौता दिया है। मैं इसे 1992 में कांग्रेस सरकार द्वारा पहली बार चलाई गई "पूर्वोन्मुख नीति " के महत्वपूर्ण और सफल नतीजे के रूप में देखता हूं। पचास सालों में पहली बार सऊदी अरब के महामहिम शाह अब्दुला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-सौद की हाल की भारत यात्रा ने एक इतिहास रचा है। महामहिम और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दिल्ली घोषणा-पत्र से हमारे सभ्यताई संबंधों का एक नया अध्याय खुला है।

हमने सभी बड़ी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और जापान के साथ भी अपने संबंध सुधारे हैं और इनके साथ हमने नई स्ट्रेटजिक भागीदारियां की हैं। अगले कुछ हफ्तों में फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों का भारत आगमन हो रहा है। मैं उनकी भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में की कई नई पहलों से भारत को बहुत लाभ होगा।

अंत में, मैं इस तथ्य की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे सभी बृहत-आर्थिक संकेत ठोस हैं और अगले वर्ष भी 7.0% से अधिक की विकास दर की ओर इशारा करते हैं। हमारी सरकार सम्मिलित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और शासन के सभी स्तरों में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्प है। हम अपने लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को इस्तेमाल में लाने और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

धन्यवाद।